

पहला कॉलम



अरुणाचल में लगातार बारिश से भूस्खलन, सड़क संपर्क टूटा

ईटानगर।

अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश से भूस्खलन के बाद सड़कों से संपर्क टूट गया है। पश्चिम सियांग जिले के आलो से शियोमी जिले में मेचुखा तक की एक प्रमुख सड़क रोड़ंग और पेने गांव के बीच क्षतिग्रस्त हो गई। शियोमी जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। सीमा सड़क संगठन ने सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है और मशीनों की मदद ली जा रही। यदि मौसम सही रहा तो शनिवार शाम तक हल्के मोटर वाहनों के लिए सड़क को खोल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सियांग जिले के तारक गांव के पास पासीघाट-पगिन-आलो सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते कई वाहन फंस गए हैं। ईटानगर में जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग-415 के किनारे अवैध निर्माण के खिलाफ एक अभियान चलाया है। इन अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है जो नािलियों को अवरुद्ध कर रहे थे।

लेबनान में बदलते हालात परविदेश मंत्रालय सक्रिय

नई दिल्ली।

लेबनान में बदलते सुरक्षा परिदृश्य के बीच विदेश मंत्रालय ने बताया कि बेरूत में भारतीय दूतावास वहां मौजूद भारतीय नागरिकों के साथ 'लगातार संपर्क' में है और उनके लिए परामर्श भी जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यह परामर्श भारतीयों को बेरूत की यात्रा करने से रोकने वाला यात्रा परामर्श नहीं है। दरअसल कुछ खबरों में दावा किया गया था कि भारत ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। उन्होंने कहा, 'बेरूत में हमारे दूतावास ने एक परामर्श जारी किया है। बहुत सारे भारतीय नागरिक वहां रहते हैं, वहां काम करते हैं... वहां पेशेवर हैं। मेरे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक करीब दो-तीन हजार लोग वहां हैं। मंत्रालय ने कोई यात्रा परामर्श जारी नहीं किया है। परामर्श में सिर्फ इतना कहा है कि उन्हें दूतावास के संपर्क में रहना चाहिए, ताकि अगर कोई घटना हो, तब हम जल्द से जल्द कार्रवाई कर सकें।' लेबनान की सीमा दक्षिण में इजरायल से लगती है। दूतावास ने अपने परामर्श में लिखा, "लेबनान में वर्तमान स्थिति को देखकर लेबनान में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और हमारे ईमेल या आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से बेरूत में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें।

नकारा कर्मचारियों और अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों को परिपत्र जारी किया है। जुलाई माह से हर महीने की 15 तारीख को नकारा कर्मचारियों और अधिकारियों की सूची भेजने के लिए कहा है। निर्देशों का पालन नहीं करने और समय पर कार्य नहीं करने पर, हर माह उनके नाम सूची में शामिल कर भेजने के लिए निर्देश जारी किए हैं। ऐसे नकारा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पहले कंपलसरी रिटायरमेंट की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 27 जून को कार्मिक मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों को परिपत्र भेजा गया है। हर माह कर्मचारियों की समीक्षा करने के निर्देश सभी मंत्रालयों को दिए गए हैं। हर माह की 15 तारीख को कार्मिक मंत्रालय में सूची भेजने का निर्देश विभागाध्यक्षों को दिया गया है।

तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट....4 की मौत

चेन्नई।

तमिलनाडु के विरुधनगर में एक पटाखा निर्माण इकाई में विस्फोट के बाद 4 श्रमिकों की मौत हुई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि श्रमिकों की मौतें पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि विस्फोट और आग लगने का कारण पटाखा बनाने में रासायनिक पदार्थों का गलत तरीके से इस्तेमाल होना बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इकाई के नजदीक मौजूद एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। उन्होंने बताया कि पटाखा निर्माण इकाई की इमारत को भी इस घटना में नुकसान पहुंचा है।



केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब, अब तक 10 लाख ने किए दर्शन

देहरादून। (एजेंसी)

उत्तराखंड में स्थित बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है। मानसून के दस्तक देने के बावजूद हजारों की संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं। 10 मई से शुरू हुई यात्रा में अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस बार बाबा की यात्रा दर से शुरू हुई, इसके बाद भी भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। पहले दिन से ही आस्था का सैलाब केदारपुरी में देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कपाट खुलने के



पहले दिन 20 हजार से ज्यादा श्रद्धालु इसके साक्षी बने थे। यात्रा के संपन्न होने में अभी भी चार महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में बताया जा रहा है कि अंत तक धाम के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 25 लाख के पार पहुंच सकती है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसका जिला प्रशासन पूरा ध्यान

रख रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उनके उतरने के लिए व्यवस्था की गई है। पैदल मार्ग और धाम में रैन शेल्टर बनाए गए हैं। ट्रेफिक जाम से निजात पाने के लिए जगह-जगह पर बैरिकेडिंग भी की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इस बार यात्रा में मुख्य बात यह है कि पशुओं का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़े-खच्चरों के आगम के लिए टिन शेड बनाया गया है। पहले इन पशुओं के आगम के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।

कम कार्बन उत्सर्जन, मोदी सरकार की पहल को मदद देगा विश्व बैंक

1.5 अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी



नई दिल्ली। (एजेंसी)

विश्व बैंक ने कम कार्बन उत्सर्जन वाले ऊर्जा उत्पादन के विकास में तेजी लाने के तहत दूसरे ऑपरेशन के तहत भारत को 1.5 अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने बताया कि 'लो-कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन' का दूसरा चरण ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सुधारों में मददगार होगा, जो

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तकनीक है। यह ऑपरेशन सरकार की ऊर्जा सुरक्षा और विश्व बैंक की हाइड्रोजन फॉर डेवलपमेंट (एच4डी) भागीदारी के अनुरूप है। विश्व बैंक के अनुसार, सुधारों के परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2025-26 से प्रति वर्ष करीब 4,50,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन और 1,500 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर का उत्पादन होने की उम्मीद है। इसके अलावा, यह अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन में प्रति वर्ष पांच करोड़ टन कमी लाने में भी महत्वपूर्ण रूप से मदद करेगा। यह ऑपरेशन राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार को विकसित करने में समर्थन करेगा। भारत में विश्व बैंक के निदेशक ऑगस्ट तानो कुआमे ने कहा, विश्व बैंक को

भारत की लो-कार्बन विकास रणनीति का समर्थन जारी रखने की प्रसन्नता है, जो देश के शुद्ध-शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा और निजी क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नौकरियां पैदा करेगा। ऑपरेशन के लिए टीम लीडर की भूमिका निभाने वाले ऑरिलियन क्रूस, शियाओडोंग वांग और सुरभि गोयल ने कहा, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए घरेलू बाजार विकसित करने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं, जो तेजी से विस्तारित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पर आधारित है। विश्व बैंक ने जून 2023 में 1.5 अरब डॉलर के पहले ऑपरेशन को मंजूरी दी थी, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन शुल्क की छूट, सालाना 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा निविदाएं शुरू करने के लिए एक स्पष्ट राह तैयार करना और राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार के लिए एक कानूनी ढांचा बनाना शामिल है।

सोनिया गांधी का पीएम मोदी पर हमला, सहमति की बात करते हैं.....टकराव के रास्ते पर

नई दिल्ली। (एजेंसी)

18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। इस बार जहां संसद में सत्ता पक्ष पहले से कुछ कमजोर हुआ है, वहीं विपक्ष मजबूत हुआ है। अब इसका असर लोकसभा सत्र के दौरान दिख रहा है। हालांकि मोदी सरकार के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर हमलावर हैं। लेकिन विपक्ष भी नोट पेपर लीक पर मोदी सरकार की गेराबंदी में जुटा है। पीएम मोदी के आपातकाल के जिक्र के बाद फिर राजनीतिक भूचाल आ गया है। इस बीच कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लेख लिखकर मोदी सरकार पर जमकर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने लेख में कहा कि '2024 के चुनाव में पीएम की



व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार हुई है। पीएम मोदी सहमति की बात करते हैं लेकिन टकराव का रास्ता अख्तियार करते हैं। सोनिया गांधी ने लिखा है मोदी सरकार की ओर से जब विपक्ष से स्पीकर चुनाव में समर्थन की मांग की गई, तब परंपरा के मुताबिक उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। बल्कि पीएम मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र कर आश्चर्यजनक रूप से स्पीकर ने भी ध्यान भटकने के लिए बड़ी किया। सोनिया ने अपने लेख में लिखा

नीट घोटाले पर, जिसने हमारे लाखों युवाओं के जीवन पर कहर बरपाया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तत्काल प्रतिक्रिया यह थी कि जो कुछ हुआ है, उसकी गंभीरता को नकार दिया जाए। पीएम मोदी जो अपनी 'परीक्षा पे चर्चा' करते हैं, वे देश भर में इतने सारे परिवारों को तबाह करने वाली लोक पर स्पष्ट रूप से चुप हैं। उन्होंने लिखा इस बीच, भारत के अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और धमकी का अभियान एक बार फिर तेज हो गया है। सोनिया गांधी ने लेख में लिखा मणिपुर जलता रहा लेकिन प्रधानमंत्री वहां जाने का समय नहीं निकाल सके। प्रधानमंत्री के 400 पार के नारे को जनता ने रिजेक्ट किया इस पर उन्हें आत्म विश्लेषण करना चाहिए।

नीतीश का ऐलान, अब हमेशा एनडीए गठबंधन का रहेंगे हिस्सा

-जेडीयू ने सांसद संजय झा को बनाया पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष

पटना। (एजेंसी)



बिहार में सत्तारुढ़ गठबंधन का नेतृत्व कर रहे जनता दल यूनाइटेड ने आज अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अहम फैसले लिए। बिहार के सीएम और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सांसद संजय झा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि वह अब हमेशा एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। माना जा रहा है कि नीतीश के इस ऐलान से उन अटकलों पर विराम लग गया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि वह दोबारा इंडिया गठबंधन में लौटने की राह तलाश रहे हैं। बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि सीएम

नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है कि अब वे हमेशा एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार हाईकोर्ट द्वारा रोके गए आरक्षण को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने यह कहा कि राज्यसभा सांसद संजय झा को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी का अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी ने बिहार को विशेष दर्जा या विशेष वित्तीय पैकेज देने की केंद्र सरकार से मांग की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जद (यू) ने पेपर लीक मामले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए संसद में कठोर कानून बनाने की भी मांग की है। बता दें कि दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के सभी सांसद, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर बिहार और अन्य राज्यों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के विश्लेषण के साथ ही 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।

-दौलत बेग ओल्डी इलाके में टैंक अभ्यास करते समय हुआ हादसा

लद्दाख में एलएसी के पास अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से पांच जवान शहीद

नई दिल्ली, (एजेंसी)।

लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में देर रात एक दुखद दुर्घटना घटी। रात 3 बजे टैंक अभ्यास के दौरान नदी पार करते समय अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया जिसमें सेना के जवान फंस गए। इस हादसे में सेना के पांच जवान शहीद हो गए हैं और एक जवान को बचा लिया गया। दरअसल शुक्रवार-शनिवार की रात में दौलत बेग ओल्डी में टैंक अभ्यास चल रहा था और सेना के कई टैंक यहां मौजूद थे।

इस दौरान एलएसी के पास एक टी-72 टैंक ने रात में नदी कैसे पार की जाती है इसका अभ्यास चल रहा था। रक्षा अधिकारी ने बताया कि दौलत बेग ओल्डी इलाके में नदी पार करने के अभ्यास के दौरान हुए हादसे में एक जेसीओ और चार जवान समेत भारतीय सेना के पांच जवान शहीद हो गए। सभी पांचों के शव बरामद कर लिए गए हैं। टैंक की बरामदगी की भी कोशिश की जा रही है। सेना इस बात की जांच कर रही है कि अचानक से जलस्तर

कैसे बढ़ गया। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां पर भारत और चीन के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताया है। राजनाथ सिंह ने पोस्ट में लिखा, लद्दाख में नदी पार करते समय हुए हादसे में भारतीय सेना के पांच जवानों की जान जाने से मैं बहुत दुखी हूं। हम देश के लिए अपने वीर जवानों की अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। दुख की इस घड़ी में

पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अभ्यास के दौरान जब एक टैंक नदी को पार करने की कोशिश करने लगा तो अचानक से नदी का जलस्तर तेज हो गया और टैंक बह गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान टैंक में कुल 4-5 जवान सवार थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, लद्दाख में एक नदी पार करते समय एक जेसीओ सहित पांच भारतीय सेना के जवान की जान जाने से हम



बहुत दुखी हैं। इस घटना के शिकार हुए सेना जवानों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। दुख की इस घड़ी में, पूरा देश हमारे वीर सैनिकों की अनुकरणीय सेवा के लिए उन्हें सलाम करता है।

संपादकीय

बारिश का एक दुख

पहली बारिश में ही दिल्ली का जो हाल हुआ है, वह न केवल चिंताजनक, बल्कि दुःखद भी है। जगह-जगह जाम, जल भराव, पेड़ों का गिरना अपनी जगह बहुत गंभीर है, पर सबसे सनसनीखेज घटना नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल- 1 पर घटी है। शुक्रवार को भारी बारिश के बीच छत का एक हिस्सा वाहनों पर आ गिरा, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। जब हादसा हुआ, तब बारिश हो रही थी, सुबह करीब 5.30 का समय था, हादसा अकल्पनीय था। बीते मार्च में ही नई दिल्ली के सबसे बड़े हवाई अड्डे के टर्मिनल- 1 का विस्तार किया गया है। इसका विस्तार करने- कराने वालों ने सुंदरता का तो ध्यान रखा, मगर मजबूती सुनिश्चित करना शायद वे भूल गए। इस टर्मिनल से लाखों लोग यात्रा करते हैं, पर रखरखाव में ऐसी लापरवाही अक्षम्य मानी जाए, तो ही न्याय है। एक बार सोचकर जरूर देखना चाहिए कि दुनिया में क्या संदेश गया है? क्या भारत अपने एक सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे को भी ढंग से नहीं रख पा रहा है? राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट पर जब यह हाल है, तो बाकी जगहों पर आम लोगों की सुरक्षा को लेकर न जाने कितने सवाल खड़े किए जा सकते हैं? न जाने कितने ऐसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे होंगे, जिन्हें सिर्फ रंग-रोगन करके चमकाया गया होगा? जिम्मेदार अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए, उनकी लापरवाही के चलते भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है? कहीं भवन ढह रहे हैं, तो कहीं पुल गिर रहे हैं, तो कहीं सड़कों पर दरारें पड़ रही हैं? खूब लंबे-चोड़े राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना जरूरी है, पर शहरों के अंदर की सड़कों का रखरखाव कौन करेगा? दिल्ली में केवल दो घंटे की बारिश के बाद अंडरपास और अंडर ब्रिज में पानी भर जाना क्या हमारी अक्षम नौकरशाही की और इशारा नहीं है? नौकरशाहों को भला कैसे निर्दोष मान लिया जाए और अगर उन्हें निर्दोष मान लिया जाए, तो फिर दोषी कौन है? यह शर्मनाक बात है कि राष्ट्रीय राजधानी में स्थित मिंटो ब्रिज दशकों से लोगों को रूलाता आ रहा है, वहां से तमाम नेताओं, अफसरों, रसूखदारों की गाड़ियां गुजरती हैं, पर क्या मजाल कि मिंटो ब्रिज इलाके में पानी न भरे? देश में ऐसे न जाने कितने स्थान हैं, जिनके बारे में यह मान लिया गया है कि यहां तो जल भराव एक सालाना आयोजन है। साल में दस-पंद्रह दिन जल भराव होगा, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या जहमत उठाए? क्या हम अपने देश में नागरिक सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं? क्या अपने देश में लोगों की जिंदगी को बहुमूल्य माना जाता है? इस बार भी उदरता से मुआंजा दे दिया जाएगा, पर पुख्ता समाधान व सुरक्षा के इंतजाम के प्रति लापरवाही बरती जाएगी? यह दोषारोपण करने या आखें चुराने का नहीं, बल्कि कमियों से दो-दो हाथ करने का वक्त है। सुविधाओं का विस्तार जरूरी है, लेकिन उनकी गुणवत्ता भी काबिले-गौर होनी चाहिए। गुणवत्ता या कानून से समझौता करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था गतिवान है, वस्तुओं और सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है, पर अगर हम अपने नागरिकों की कद्र नहीं बढ़ाएंगे, तो वास्तव में विकास को ही अंगूठा दिखाएंगे। दुनिया के अच्छे देशों से सीखते हुए सुधार की जरूरत है, ताकि हमारा बेहद चमकदार होता बुनियादी ढांचा हमारे माथे पर ही न गिरने लगे और हम आश्चर्य होकर सिर उठाए चल सकें।

आज का राशीफल

मे़ष	संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। वाणी की सौम्यता बनाये रखने की आवश्यकता है।
वृषभ	पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। यात्रा में अपने सामान के प्रति सचेत रहें चोरी या खोने की आशंका है। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। धन हानि की संभावना है।
मिथुन	जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। भारी व्यय का सामना करना पड़ सकता है। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।
कर्क	व्यावसायिक व पारिवारिक योजना सफल होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। नए अनुबंध प्राप्त होंगे।
सिंह	व्यावसायिक योजना सफल होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। वाद विवाद की स्थिति आपके हित में न होगी। मकान, सम्पत्ति व वाहन की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा।
कन्या	बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। पारिवारिक जनों के मध्य सुखद समय गुजरेगा। वाणी की सौम्यता आपको प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।
तुला	आर्थिक योजना को बल मिलेगा। पिता या उच्चाधिकारी से तनाव मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। विरोधी परास्त होंगे। धन लाभ होने के योग हैं।
वृश्चिक	जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। यात्रा दशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।
धनु	आर्थिक दिशा में प्रगति होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। व्यर्थ की भावदीडु रहेगी।
मकर	पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। राजनैतिक क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे। वाणी की सौम्यता आपको लाभ दिलायेगी। भारी व्यय का सामना करना पड़ सकता है। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।
कुम्भ	पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। खान-पान में संयम रखें। जीविका की दिशा में प्रगति होगी। विरोधी परास्त होंगे। ससुराल पक्ष से लाभ होगा।
मीन	जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। मित्रों या रिश्तेदारों से पीड़ा मिलेगी। नेत्र विकार की संभावना है। आय के नवीन स्रोत बनेंगे।

विचार मंथन

(लेखक-सनत जैन)

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा, अदालत में जो दस्तावेज ईडी द्वारा पेश किए गए हैं, उन दस्तावेजों से कहीं पर भी हेमंत सोरेन दोषी प्रमाणित नहीं होते हैं। भूमि अधिग्रहण और कब्जे के मामले में हेमंत सोरेन की कोई भागीदारी हाईकोर्ट को नहीं मिली। हाईकोर्ट ने जमानत के फैसले में कहा, याचिकाकर्ता को जमानत देने से कोई हानि होने वाली नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विवादित 8।86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण, कब्जे और आय से जुड़े होने का कोई प्रमाण ईडी प्रस्तुत

नहीं कर पाई। 2010 में जब उक्त भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उस समय हेमंत सोरेन की सरकार भी नहीं थी। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा, ईडी ने ऐसा कोई भी प्रमाण पेश नहीं किया, जिससे यह साबित हो, कि याचिकाकर्ता हेमंत सोरेन ने जमीन पर कब्जा किया है। उन्हें कोई आय प्राप्त हुई हो। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया पीएमएलए एक्ट के तहत कोई मामला नहीं होने के कारण, हेमंत सोरेन को जमानत दी है। लगभग 5 महीने हेमंत सोरेन जेल में बंद रहे। उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। समय-समय पर ईडी के समन का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्हें बार-बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दौड़ना पड़ा। लाखों रुपए उनके और करोड़ों रुपए

सरकार के खर्च हुए। कई महीनों तक हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी और दोषी बताया गया। लोकसभा चुनाव में उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोका गया। एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें काम करने से रोका गया। जनता ने उन्हें विधायक और मुख्यमंत्री के रूप में चुना था। वह अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाए। ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के महीनो चक्कर लगाने के बाद भी हेमंत सोरेन जमानत पर वापस आए हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें पीएमएलए कानून से निर्दोष घोषित नहीं किया है। पीएमएलए कानून का यह मुकदमा कितने साल तक चलेगा। भगवान ही इसका मालिक है। भारतीय जनता पार्टी और उनके विपक्षी राजनेता हमेशा उन्हें जमानत पर छूटे अपराधी के तौर पर उन पर हमला करते

रहेंगे। व्यक्तिगत, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता रहेगा। जमानत के मामले में हेमंत सोरेन ने ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के कई चक्कर जमानत पाने में लगा दिए हैं। प्रथम दृष्टया कोई अपराध प्रमाणित नहीं होने के बाद भी उन्हें वर्षों मुकदमा लड़ना पड़ेगा। हेमंत सोरेन राजनीतिक और आर्थिक रूप से समर्थ हैं। मुकदमा लड़ने की उनकी हैसियत भी है। आम आदमी अपना बचाव किस तरह से जांच एजेंसियों के उरपीड़न से कर पाएगा? जब संविधान ने नागरिकों को जमानत का अधिकार दिया हुआ है। जेल को अपवाद माना गया है। पिछले कुछ वर्षों में जांच एजेंसियों द्वारा पीएमएलए, यूपीए कानून के तहत लोगों को गिरफ्तार करके

जेल भेज दिया जाता है। कई वर्षों और कई महीनो तक उन्हें जेल में बंद रखा जाता है। दोनों कानून में न्यायालय द्वारा जमानत नहीं दी जाती है। कई वर्षों तक जांच एजेंसी जांच पूर्ण नहीं करती है। आरोपियों को बिचाराधीन कैदी के रूप में जेल में लंबे समय तक बंद रखा जाता है। मीडिया ट्रायल में आरोपियों की सामाजिक, राजनीतिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। आर्थिक नुकसान अलग होता है। पूरे परिवार पर इसका असर पड़ता है। इस तरह की कार्रवाई पर जब तक जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी। इसी तरह से कानून का दुरुपयोग होता रहेगा। सत्ता में बैठे हुए लोग यदि कानून का इस तरह से दुरुपयोग करेंगे। जो



प्रमाणित भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में जांच एजेंसी के अधिकारियों को जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। ताकि वह सत्ता में बैठे हुए राजनेताओं के दबाव में अधिकारों का दुरुपयोग ना कर पाएं। तभी भारतीय संविधान, भारतीय न्याय व्यवस्था, भारतीय सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को विश्वास योग्य बनाया जा सकता है।

नीट पेपर से लेकर छतों तक लीक ही लीक

(लेखक - राकेश अचल)

7 हम जब बच्चे थे तब जिस लीक के बारे में जानते थे,वो आजकल के पेपर लीक और छत लीक से एकदम अलग थी । अंग्रेजी की लीक और हिंदी की लीक में जमीन – आसमान का अंतर होता है । अंग्रेजी की लीक को हमारे यहां हिंदी में ही नहीं बल्कि बुंदेलखंडी में भी टपकना या चूना कहते हैं। हमारे यहां लीक का दूसरा अर्थ पगड़णी भी होता है और एक अर्थ सिर में पड़ने वाले जुओं के बच्चे भी होते हैं। ये सफेद रंग के होते हैं। कहावत है कि – लीक लीक कायर चले और लीक चले कपूत, लीक छोड़ तीन ही चले शायर, सिंह , सपूत। आज दुर्भाग्य से कहिये या सौभाग्य से लीक यानि लीकेज एक राष्ट्रीय समस्या है । सड़क से लेकर संसद तक इस लीक की चर्चा हो रही है। लेकिन संसद में लीक पर चर्चा की इजाजत देने के बजाय बहस की मांग करने वाले विपक्ष के नेता का माइक तक बंद किया जाने लगा है। अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अधिकार का गला घोटो जा रहा है। गला घोटना एक जुलाई से लागू होने वाली भारतीय न्याय संहिता के तहत तहत किस धारा में अपराध होता है ये अभी मुझे पता नहीं ,क्योंकि मैंने जो संहिता अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी थी वो भारतीय दंड संहिता थी।

सबसे पहले अयोध्या में नव निर्मित राम मंदिर की छत से होने वाली लीकेज की बात की जाये । चूंकि हम अयोध्या से सैकड़ों किमी दूर बैठे हैं इसलिए हमें सच्चाई का पता नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें वायरल हुई हैं उनकी बिना पर हम कह रहे हैं कि राम जी के मंदिर की छत लीक हो रही है । लेकिन मंदिर के ट्रस्टी कह रहे हैं कि –ये अपवाद है। अब हम तस्वीरों को सही मानें या ट्रस्टियों की बात को ये भी हमें पता नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा साक्ष्य नए साक्ष्य संहिता की किस धारा के तहत आता है ?

वैसे अयोध्या में राम मंदिर के लीकेज से पहले यहां भाजपा की छत में भी लीकेज हुआ है और राम जी ने इसकी सजा भाजपा को यानि मंदिर निर्माण करने वाली राष्ट्रहितैषी पार्टी को चुनाव हारकर दे दी है। ये बात और है की भाजपा इस सजा को भी राम जी का प्रसाद और अनुकम्पा मानती है। ये भाजपा की और चमत्त राय की दरियादिली है। आजकल की अवातव की चर्चाओं में दरियादिली की सख्त जरूरत है। विपक्ष ने भी लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में मतदान न कराकर दरियादिली का मुजाहिदा किया ही है।

अयोध्या से यदि आप दिल्ली आए तो यहां अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गाँधी हवाई अड्डे पर टर्मिनल –1 की छत लीक हो रही है और पार्किंग की छत तो टपक ही गयी। मेरा मानना है कि इसके लिए इंदिरा गाँधी ही जिम्मेदार निकलेंगी । यदि उनके नाम की वजाय ये हवाई अड्डा किसी भाजपा नेता के नाम पर होता तो शायद न छत लीक होती और न छत टपकती। वैसे पीने के पानी को लेकर हाय ! हाय !! कर रही पूरी दिल्ली ही इस समय लीक हो रही है । आम आदमी से लेकर ख़ास

आदमियों के घर में पानी घुस चुका है । सड़कें यमुना की सगी बहनों की तरह सड़कों पर बह रही है। किसी की क्या मजाल की कोई इस पानी को रोक सके । पानी को रोकने के लिए तो कोई स्विच भी नहीं होता अन्यथा सरकार ओम बिरला ने जिस तरह से राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी ठीक उसी तरह पानी की बोलती भी बंद करा देती।

लीकेज और टपका-टपकी केवल दिल्ली का ही मसला नहीं है। हमारे मध्यप्रदेश में जहां डबल इंजिन की सरकार है वहां भी जबलपुर में हवाई अड्डे का पोर्व एक कर के ऊपर आ गिरा। कार का कचूमर निकल गया ठीक उसी तरह जिस तरह देश की जनता का कचूमर पिछले एक दशक से निकल रहा है और जनता है कि मुस्कराये जा रही है ,फिर से पुरानी सरकार को सतारुद्ध देखकर। अब जबलपुर में हवाई अड्डे का पोर्व टपकने के लिए हमारे पहलवान मुख्यमंत्री डॉमोहन यादव को तो जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता । इसके लिए तो पूर्व के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही दोषी माना जाना चाहिए ,लेकिन कर-चोर मोसरे भाई होते है। कौन –किसे जिम्मेदार ठहराए इसको लेकर भी विवाद खड़ा हो सकता है।

अब आइये बिहार चलते हैं। यहां नालंदा विश्व विद्यालय को नव जीवन दिया गया है। यहां से ही नीट का पेपर लीक हुआ है जो हमारी मोश्रा सरकार के गले की हड्डी बन गया है। चूंकि बिहार सरकार की बैशाखी पर मोश्रा की सरकार टिकी है इसलिए नीट पेपर लीक को लेकर सरकार संसद में बहस करने से कन्नी काट रही है। कन्नी होती ही काटने के लिए है। बिहार में पेपर ही लीक नहीं होते बल्कि पूरे के पूरे पुल ही बह जाते है। अभी तक तीन-चार पुल तो बह चुके है। अब भाजपा और जेडीयू के बीच जो नया पुल बना है वो कितने दिन टिकेगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। माननीय गारंटी महोदय भी नहीं। बिहार का और गारंटी का कोई रिश्ता नहीं है। बिहार न नीतीश कुमार की गारंटी दे सकता है और न तेजस्वी यादव की। चिराग पासवान हों या जीतन माझी। कोई भी गारंटी देने का खतरा मोल नहीं ले सकते। पता नहीं कब,किसे ,किसके साथ खड़ा होना पड़े ?

वैसे लीकेज सचमुच है ही विश्वव्यापी समस्या । आपको याद है न कि एक विकीलीक्स हुआ करती है ,जो दुनिया भर की सरकारों के बारे में न जाने क्या-क्या लीक करती रहती है। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे हैं। वे अक्सर जेल आते-जाते रहते हैं। पिछले दिनों अमेरिका ने उन्हें अपनी जेल से रिहा कर दिया। अमेरिकी न्याय विभाग के साथ हुई डील के बाद उन्हें लंदन की हाई सिक्वोरिटी जेल से छोड़ दिया गया है। रिहाई के बाद असांजे अपने मूल देश ऑस्ट्रेलिया चले गए। लेकिन हमारे देश में किसी भी लिक्बाज को न पकड़ा जाता है और न सजा होती है ,क्योंकि हमारे यहां लीक करना एक कुटीर उद्योग है। ये यूपी,बिहार,मध्यप्रदेश,राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली तक में



बाकायदा सरकारी संरक्षण में पनपता है ,भले ही सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की। लीकेज का धंधा बिना सरकारी सारंक्षण के चल ही नहीं पाता ,लेकिन इस हकीकत को हमारी संसद सुनना नहीं छति और सरकार स्वीकार करना नहीं चाहती।

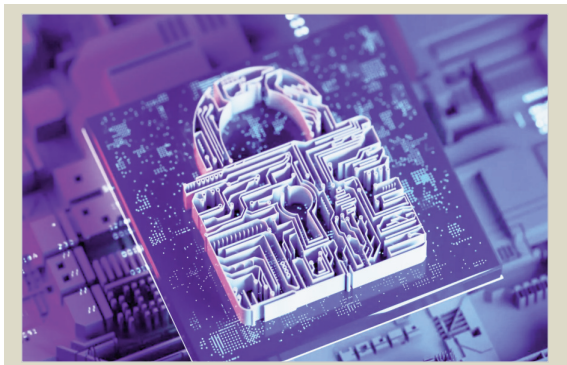
मेरा तो मशवरा है कि न सिर्फ केंद्र में बल्कि राज्य में लीकेज की समस्या को देखते हुए एक पृथक मंत्रालय की स्थापना कर देना चाहिए। एक अलग मंत्री लीकेज के मामले को देखे । रोज-रोक सीबीआई कहीं तक लीकेज के मामले दिखेगी ? सीबीआई के पास विपक्षियों की घर-पकड़ का इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम पहले से ही है। मैं तो कहता हूँ कि उन्हें भी लीकेज के मामले में संसद पर बहस करने पर जोर नहीं देना चाहिए,उन्हें सड़कों पर उतर कर पीड़ितों के बीच खड़े होकर संसद के बाहर लीक काण्ड पर बहस करना चाहिए। संसद भीतर की बहस से नहीं बल्कि बाहर होने वाली बहस से हिलती है। भीतर तो उनका माइक सरकार बंद करा सकती है किन्तु बाहर ऐसा करना सरकार के लिए भी मुमकिन नहीं है।

आपकी हो या न हो किन्तु मेरी स्पष्ट धारणा है कि देश की संसद हो या सरकार ,पुल हो या हवाई अड्डा,परीक्षा हो या चुनाव सबके सब लीक प्रूफ होना चाहिए। लीकेज को राष्ट्रीय उद्योग न बनाकर राष्ट्रीय अपराध बनाया जाना चाहिए। वैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने ऐसे कानून एहतियत के तौर पर बनाये हैं ,सरकार चाहे तो इन लीकबाजों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता,भारतीय साक्ष्य संहिता में भी तरमीम कर सकती है और इसके आरोपियों के खिलाफ बुलडोजरों का इस्तेमाल भी कर सकती है ,लेकिन मुझे पता है कि ऐसा करने के लिए चार सौ पार वाली सरकार चाहिए। 240 पार वाली सरकार ये सब नहीं कर सकती। बहरहाल हम देश के नीजवानों के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि उनकी परीक्षाओं के पेपर लीक न हों । हम देश के हवाई अड्डों ,पुलों, मंदिरों और नई नवेली संसद के लिए भी प्रार्थना ही कर सकते हैं कि वे न लीक हों और न टपकें और न बहें। हम नहीं जानते कि प्रार्थनाओं में कितना दम होता है ,लेकिन हमें इसके अलावा कुछ और आता ही कहीं है ?

आज़ादी के बाद से लोकसभा अध्यक्ष का निवास

शताब्दी वर्ष में 20 अकबर रोड/ विवेक शुक्ला

ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। इस तरह उनका राजधानी के 20 अकबर रोड पर ही सरकारी आवास रहेगा। पहली लोकसभा के 1952 में गटन के साथ ही जामुन और अमलतास के पेड़ों से लबरेज अकबर रोड के 20 नंबर के बंगले का भारतीय संसद के निचले सदन से अटूट संबंध कायम हो गया था। वो रिश्ता अब भी बना हुआ है। दरअसल, 1952 में कांग्रेस के गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रोड का बंगला आवंटित हुआ। उसके बाद इसी डबल स्टोरी बंगले में लोकसभा अध्यक्ष रहते रहे। मावलंकर जी के 1956 में निधन के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनके स्थान पर कांग्रेस के ही अनंतशयनम अयंगार वासुदेव मावलंकर लोकसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। मावलंकर जी को 20 अकबर रो



पिछले 20 वर्षों में वित्तीय क्षेत्र पर 20,000 साइबर हमले हुए

मुंबई ।

आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में वित्तीय क्षेत्र पर 20,000 से अधिक साइबर हमले हुए, जिसके परिणामस्वरूप 20 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। डेटा सिक्नोरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऐसे 25 फीसदी हमले ईमेल और वेबसाइटों में दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करने से होते हैं। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा गया है कि वित्तीय संस्थानों पर साइबर हमलों के 69 प्रतिशत मामले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा, 19 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों द्वारा और 12 प्रतिशत गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा रिपोर्ट किए गए। इसके कारण बैंकों ने 2023-24 में अपने बीमा कवर को पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8 फीसदी बढ़ा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थानों को जारी परामर्श में कहा गया है कि संभावित साइबर हमलों के संबंध में प्राप्त विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के मद्देनजर विनियमित संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वे इन खतरों से बचाव के लिए निगरानी और तत्पकता क्षमताओं को उन्नत करें।

नोएडा फिल्म सिटी से 50,000 रोजगार के अवसर मिलेंग: यूपी सरकार

नोएडा ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी परियोजना का निर्माण छह महीने के भीतर शुरू हो सकता है और इससे 50,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा लगभग सात लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से भी लाभान्वित होंगे। फिल्म निर्माता बेनी कपूर और रियल एस्टेट डेवलपर आशीष भूटानी द्वारा समर्थित गठजोड़ बेव्यू प्रोजेक्ट्स ने फिल्म सिटी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण छह महीने के भीतर शुरू हो जाएगा और तीन साल के भीतर यहां फिल्म शूटिंग और संबंधित गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी। सरकार ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य फिल्म उद्योग में अवसर चाहने वाले राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई जैसे स्थापित केंद्रों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करना है।

बंगाल सरकार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दैनिक कामकाजी समय बढ़ाएगी

कोलकाता ।

पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में एक जुलाई से दैनिक कामकाजी घंटों की सीमा 30 मिनट बढ़ाने जा रही है। राज्य के आईटी उद्योग मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस निर्णय के साथ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि हालांकि सप्ताह में अधिकतम 48 कामकाजी घंटों की सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी कर सकती है। सुप्रियो ने कहा कि अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा में लालमेल बनाए रखने और पश्चिम बंगाल के आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दैनिक कामकाजी समय सीमा को 8.30 घंटे से बदलकर नौ घंटे करने को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक कामकाजी योजना के सदस्य भी ईपीएस खाते से पैसे निकाल पाएंगे। इस संशोधन से प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से अधिक ऐसे सदस्यों का लाभ होगा जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं।प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के अनुसार केंद्र सरकार ने टेबल डी को भी संशोधित किया है। अब से

सरकार ने ईपीएस से पैसे निकालने का बदल दिया नियम - कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ होगा

नई दिल्ली ।

सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैसे निकालने के नियम बदल दिए हैं। इस संसोधन के बाद 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य भी ईपीएस खाते से पैसे निकाल पाएंगे। इस संशोधन से प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से अधिक ऐसे सदस्यों का लाभ होगा जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं।प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के अनुसार केंद्र सरकार ने टेबल डी को भी संशोधित किया है। अब से

विज्ञॉल बनेफिट इस बात पर निर्भर करेगा कि सदस्य ने कितने महीने तक सर्विस किया है और वेतन पर कितना ईपीएस का योगदान किया जाता रहा है। इससे सदस्यों के विज्ञॉल बनेफिट को तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी। इस संशोधन से 23 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को लाभ होगा। श्रम मंत्रालय ने बताया कि देश में लाखों ऐसे ईपीएस 95 स्कीम के सदस्य हैं जो पेंशन पाने के लिए 10 वर्ष तक लगातार स्कीम में योगदान करने के नियम के बावजूद बीच में ही स्कीम से बाहर आ जाते हैं। अभी तक के नियमों के मुताबिक तक विज्ञॉल बनेफिट

के कैंलकुलेशन के लिए सर्विस में पूरे किए गए वर्ष और उस वेतन के आधार पर तय किया जाता है जिस पर ईपीएस के लिए योगदान किया गया है। 6 महीने या उससे अधिक समय तक योगदान करने वाले मेंबर्स ही इस विज्ञॉल लाभ ले सकते थे।

ऐसे में जो सदस्य छह महीने से कम समय तक योगदान करने के बाद स्कीम छोड़ देते हैं उन्हें कोई विज्ञॉल बनेफिट नहीं मिलता था। इसके चलते कई लोगों के क्लेम के आवेदन को खारिज कर दिया जाता था। श्रम मंत्रालय के मुताबिक छह महीने से ऊं यादा अंशदान के नियम के चलते

2023-24 में 7 लाख विज्ञॉल क्लेम के आवेदन को खारिज कर दिया गया। ये ऐसे आवेदन थे जिसमें 6 महीने से कम समय के लिए ईपीएस 95 स्कीम में योगदान किया गया था लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद वैसे सभी ईपीएस सदस्य जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की आयु के नहीं हुए हैं। वे भी पैसे निकालने के हकदार हो जाएंगे।केंद्र सरकार ने टेबल डी को भी संशोधित किया है। अब से विज्ञॉल इस बात पर निर्भर करेगा कि सदस्य ने कितने महीने तक सर्विस किया है और वेतन पर कितना ईपीएस का योगदान किया जाता रहा है।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 653 अरब डॉलर के पार

नई दिल्ली ।

पिछले सप्ताह की गिरावट के बाद देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 जून को खत्म हुए सप्ताह में 81.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 653.71 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की जोर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.92 अरब डॉलर घटकर 652.89 अरब डॉलर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार 7 जून को 655.82 अरब डॉलर रहा था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 21 जून को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली फरिन करेंसी

एसेट्स 10.6 करोड़ डॉलर घटकर 574.13 अरब डॉलर रही। उल्लेखनीय है कि कुल विदेशी मुद्रा भंडार में एफसीए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। डॉलर में अभिव्यक्त किए जाने वाले एफसीए में यूरो, पाउंड और येन जैसे गैर अमेरिकी करेंसी में आई घट-बढ़ के प्रभावों को भी शामिल किया जाता है। आरबीआई ने कहा कि ने कहा कि रिपोर्टिंग वीक के दौरान गोल्ड रिजर्व का मूल्य 98.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 56.96 अरब डॉलर रहा। रिजर्व बैंक ने कहा कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 5.7 करोड़ डॉलर

घटकर 18.05 अरब डॉलर रहा। रिजर्व बैंक के मुताबिक रिपोर्टिंग वीक में इंटरनेशनल मोनेटरी फंड के पास भारत की रिजर्व पोलीशन 90 लाख डॉलर घटकर 4.57 अरब डॉलर रह गईं।

साथ-साथ, बैंक के खिलाफ आरोप साबित होते हैं जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना आवश्यक था। इसमें कहा गया कि बैंक यह बताने में विफल रहा कि कुछ क्रेडिट कार्ड खातों में न्यूनतम भुगतान देय की गणना करते समय कोई नकारात्मक परिशोधन नहीं था। हालांकि, आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना वैधानिक तथा

नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इसके अलावा मौद्रिक जुर्माना लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विदेशी निवेशकों के सहारे बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड

संसेक्स 210 अंकों की गिरावट के साथ 79,032 पर बंद

निफ्टी 33 अंक फिसलकर 24,010 पर बंद हुआ

मुंबई ।

पिछला सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों के लिए बेहद खास रहा, विदेशी पोर्टफो लियो निवेशकों के सपोर्ट से बाजार ने नया रिकॉर्ड स्तर बनाया। शेयर बाजार में लगातार चार दिनों दिन जोरदार तेजी रही, शुक्रवार को भी बाजार में अच्छी खासी बढ़त रही ले किन बंद होते ही बाजार रिकॉर्ड स्तर पर फिसलकर बंद हुए। पिछले सप्ताह के शेयर बाजार के पांच कारोबारी दिनों पर नजर डालें तो घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को कमजोर शुरूआत हुई। संसेक्स में शुरूआती कारोबार के दौरान 316.10 अंक फिसलकर 76,903.35 पर खुला और 131.18 अंकों की बढ़त के साथ 77,341.08 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 110.85 अंकों की गिरावट के साथ

23,390.25 के स्तर पर खुला और 36.75 अंक मजबूत होकर 23,537.85 के स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार के कारोबारी सत्र के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों के शेयरों में अच्छी मजबूती दिखी। संसेक्स 523.54 अंकों की बढ़त के साथ के 77,864.62 स्तर पर खुला और 712 अंकों की बढ़त के साथ 78,053.52 पर बंद हुआ। निफ्टी 131.20 अंक उछलकर 23,669.05 के स्तर पर खुला और 83.46 अंक मजबूत होकर 23,721.30 के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार को संसेक्स 54.48 अंकों बढ़त के साथ 78,092.65 के स्तर पर खुला और 620.73 अंकों की मजबूती के साथ 78,674.25 पर बंद हुआ। निफ्टी 4.30 अंक चढ़कर 23,725.60 पर खुला और 147.50 अंकों की मजबूती के साथ पहली बार 23,850 का स्तर पार कर 23,868.80 पर बंद हुआ। गुरुवार को संसेक्स 124.05 अंक की गिरावट के साथ 78,550.20 अंक पर खुला और 568.93 अंकों की बढ़त के साथ

पहली बार 79,243.18 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34.00 अंक की नरमी के साथ 23,834.80 पर खुला और 175.71 अंकों की बढ़त के साथ 24,044.50 के स्तर पर बंद हुआ। शुक्रवार के कारोबारी दिन संसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ नए शिखर पर पहुंच गए। शुक्रवार को शुरूआती कारोबार में संसेक्स 265.46 अंकों की मजबूती के साथ 79,483.72 पर खुला और 210.45 अंकों की गिरावट के साथ 79,032.73 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 78.60 अंक मजबूत होकर 24,123.10 पर खुला और 33.91 अंक फिसलकर 24,010.60 पर बंद हुआ।

सरकार की सकल देनदारियां मार्च तक 3.4 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली । सरकार की कुल सकल देनदारियां दिसंबर के ओ खिर में 166.14 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2024 तक 171.78 लाख करोड़ रुपये हो गईं। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन तिमाही रिपोर्ट जनवरी-मार्च, 2024 में कहा गया कि यह आंकड़ा तिमाही आधार पर 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक समीक्षाधीन तिमाही के दौरान सार्वजनिक ऋण कुल सकल देनदारियों का 90.2 प्रतिशत था। इसमें कहा गया कि समीक्षाधीन तिमाही के दौरान, अंतरिम बजट में घोषित उधार योजना के अपेक्षा से कम रहने के चलते भारतीय घरेलू बॉन्ड के प्रतिकूल में नरमी आई। राजकोपीय घाटे के काबू में रहने, एफपीआई प्रवाह और स्थिर मुद्रास्फीति से इसमें मदद मिली। दूसरी ओर समीक्षाधीन तिमाही के दौरान अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिकूल अस्थिर रहा, जो मुख्य रूप से फेडरल रिजर्व की कार्रवाई, मुद्रास्फीति और रोजगार डेटा से प्रभावित था। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान अमेरिकी 10 वर्षीय प्रतिकूल 4.33 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक नए निर्गमों पर भारत औसत प्रतिकूल 2023-24 की तीसरी तिमाही के 7.37 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 की चौथी तिमाही में 7.19 प्रतिशत तक नरम हो गया। इसके अलावा दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गमों की भारत औसत परिक्रता 2023-24 की चौथी तिमाही में 18.75 वर्ष हो गई। यह 2023-24 की तीसरी तिमाही में 18.80 थी।

1 जुलाई से हो जाएंगे पांच बड़े बदलाव, जानना जरूरी है

- मोबाइल रिचार्ज से लेकर बैंक खाते तक होगा असर

नई दिल्ली ।

जुलाई का महीना अपने साथ कुछ बदलाव लेकर आता है। बैंक खाते से लेकर क्रेडिट कार्ड तक के नियमों का असर सीधा आम आदमी की जेब पर होने वाला है। नियमों की जानकारी न होने से कई बार आदमी को बिना वजह शूटे क चुकना पड़ सकता है। साथ ही कई बार कुछ कामों की डेडलाइन निकल जाने की वजह से वे काम रूक जाते हैं। एक जुलाई से टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सिम स्वैप फॉंड को रोकने के लिए सिम कार्ड चोरी होने या डैमेज होने की स्थिति में लॉकिंग पीरियड को सात दिन तक बढ़ा दिया है। यानी कि अब आपको सिम के लिए सात दिन इंतजार करना होगा। जुलाई में आपको अपना मोबाइल रिचार्ज कराने पर ज़े यादा पैसे देने होंगे। ऐसा इसलिए है वे योकि रिलायंस जियो, वोडाफोन-आईडिया और एयरटेल ने अपने

टैरिफ बढ़ा दिए हैं।हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी सिलेंडर और एटीएफ की कमीतों को संशोधित करती हैं। ऐसे में एक जुलाई से गैस सिलेंडर पर आपको राहत भी मिल सकती है। 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के नए नियम लागू हो जाएंगे। इसमें सभी बैंकों को क्रेडिट कार्ड पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए से प्रोसेस करना होगा। हालांकि, बैंकों ने अभी तक इन निर्देशों का पालन नहीं किया है। अभी तक सिर्फ 8 बैंकों ने ही जीबीपीएस पर बिल पेमेंट एक्टिव किया है। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है और उसे आपने लंबे समय से उपयोग नहीं किया है तो वह 1 जुलाई से काम नहीं करेगा। बैंक ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि 30 अप्रैल 2024 तक जिन खातों को इस्तेमाल किए हुए 3 साल से अधिक का वक हो गया है उस तरह के खाते को बैंक अब एक महीने के भीतर बंद कर देगा। बैंक ने ग्राहकों को अमुविधा से बचाने के लिए 30 जून 2024 तक की समयसीमा तय की है।

ज्ञान से प्यारा

बिहार में एक के बाद एक बह रहे पुल

11 दिन में 5 पुलों ने ली जल समाधि

नई दिल्ली। (एजेंसी)

बिहार में एक के बाद एक पुल जल समाधि ले रहे हैं। पिछले 11 दिनों में 5 पुल गिर गए। ताजा मामला मधुबनी का है। इस इलाके के भूतही नदी पर निर्माणाधीन पुल का गडर (बोम) गिर गया। करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस पुल का निर्माण चार वर्षों से हो रहा है। कुल 75 मीटर लंबी निर्माणाधीन पुल का 25 मीटर हिस्सा धराशायी हो गया।

27 जून को (कल ही) किशनगंज जिले में एक पुल गिर गया था। किशनगंज के जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने बताया कि बहादुरगंज प्रखंड में स्थित यह पुल 70

मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा था। यह पुल 2011 में कनकई नदी को महानंदा से जोड़ने वाली एक छोटी सहायक नदी मड़िया पर बनाया गया था।

कुछ दिनों पहले 22 जून को सीवान जिले में एक छोटा पुल ढह गया था। इससे पहले बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 23 जून को एक निर्माणाधीन छोटा पुल ढह गया था। यह घटना मोतिहारी के घोड़सहन प्रखंड में हुई। अमवा गांव को प्रखंड के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने के लिए राज्य के ग्रामीण निर्माण विभाग (आरडब्ल्यूडी) द्वारा नहर पर 16 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा था। 22 मार्च 2024 को सुपौल में कोसी नदी पर निर्माणाधीन बकौर-भेजा

घाट पुल ढह गया था। भारत माला योजना के तहत इसका निर्माण हो रहा था। 1200 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा था। बकौर-भेजा घाट पुल सामरिक नजरिए से भी बेहद अहम है। इसी तरह 4 जून 2023 को सुल्तानगंज से खगड़िया के अगुवानी गंगा घाट पर निर्माणाधीन पुल के पिलर नंबर 10, 11 और 12 अचानक गिरकर नदी में बह गए थे। 19 मार्च 2023 को बिहार के सारण जिले में एक पुल गिर गया था। बताया जाता है कि यह पुल अंग्रेजों के जमाने का था। बाढ़ के बाद पुल जर्जर हो गया था और कई जगहों पर दरारें आ गई थीं। विभाग के लापरवाही के कारण यह पुल

गिर गया। जर्जर पुल को लेकर विभाग की ओर से कोई चेतावनी भी जारी नहीं की गई थी। 19 फरवरी 2023 को पटना के बिहटा में सरमरा में फोन लेन पुल गिर गया था। वहीं बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान में कमला बलान नदी के सबाहल घाट पर ओवरलैड ट्रक की चपेट में आने से पुल गिर गया था। 15 मई 2023 को पूर्णिया में एक बड़ा हादसा हुआ था। यहां एक पुल का एक बॉक्स ब्लाई के दौरान गिर गया था। जुलाई 2022 में बिहार के कटिहार जिले में भी



एक निर्माणाधीन पुल गिर गया था और पुल गिरने से 10 मजदूर घायल हो गए थे। 18 नवंबर 2022 को बिहार के नालंदा जिले में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया था। पुल गिरने से 1 की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि यह पुल घंटिया निर्माण के कारण गिर गया था। 9 जून 2022 को बिहार के सहर्सा में एक पुल गिरने से कई मजदूर घायल हो गए।

बीते रोज पानी पानी हुई दिल्ली में फिर होगी झमाझम बारिश, पंजाब-हरियाणा और यूपी अलर्ट

नई दिल्ली। (एजेंसी)

बीते रोज दिल्ली में झमाझम बारिश हुई और बीते 88 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग ने एक जुलाई दिल्ली में भारी बारिश का अनुमान जारी किया है। मौसम का यह मिजाज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ है। आईएमडी ने शनिवार को दिल्ली में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाया है, साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं भी चलेंगी। दिल्ली में 'अर्रेंज' अलर्ट जारी किया गया है।

आईएमडी ने यह भी बताया है कि दक्षिण गुजरात और उसके आस-पास के इलाकों में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके कारण केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, विदर्भ, छत्तीसगढ़, कोकण, गोवा, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान मराठवाड़ा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, उत्तर और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में

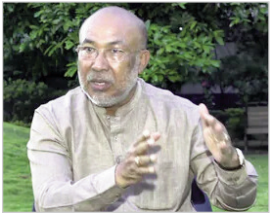
हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि 29 और 30 तारीख को छत्तीसगढ़ में अलग-अलग जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 29 जून से लेकर 3 जुलाई तक गुजरात में भी भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश में अगले पांच दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 29 और 30 जून को भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि पंजाब में 30 जून और 1 जुलाई को भारी बारिश होने का अनुमान है। 29 जून से 1 जुलाई तक हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी भारी बारिश की संभावना बताई है। उत्तर प्रदेश में 29 से 30 जून के बीच अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान में 29 जून से 2 जुलाई तक इस मौसम का सामना करने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में 29 जून को भारी बारिश होने की संभावना है।

मणिपुर में कई विधायकों ने दिल्ली में डेटा डाला, सीएम बीरेन को छोड़ना पड़ सकती है कुर्सी

इंफाल। (एजेंसी)

मणिपुर में चल रही हिंसा को रोकने में नाकाम रहे राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ सकती है। वजह ये है कि हिंसा के खिलाफ कई विधायकों ने दिल्ली में डेटा डाला हुआ है। इसी बीच अटकलें हैं कि मणिपुर में नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है। एन बीरेन सिंह सरकार के ही विधायकों के दिल्ली पहुंचने के बाद इस तरह के कयासों और भी तेज हो गए हैं। हालांकि सीएम बीरेन सिंह ने इस तरह के कयासों को फिरोती भांगी बताया है। फिरोती की कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उनके कुछ

विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। उनका दावा है कि मणिपुर में जातीय हिंसा के समाधान के लिए वह बीजेपी के दीय नेतृत्व के नेताओं से मुलाकात करने गए हैं। मणिपुर के एक मंत्री ने ही दावा किया था कि पिछले साल जून में मुख्यमंत्री ने लगभग इस्तीफा दे ही दिया था। वह अपना त्यागपत्र लेकर राजभवन पहुंच गए थे। लेकिन तभी उनके आवास के बाहर उनके समर्थन में महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाई। इसके बाद उन्होंने फैसला बदल लिया। बताया गया कि उनका त्यागपत्र दो मंत्रियों ने छीन लिया और फाड़ दिया। वे चाहते थे कि बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने रहें। बता दें कि मणिपुर की हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा की मौत हो गई है। वहीं 50 हजार लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा।



कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि मणिपुर सरकार में सहयोगी नागा पीपल्स फ्रंट, नेशनल पीपल्स पार्टी और जेडीयू मुख्यमंत्री पर इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं। खबरों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व के इस बात कि लिए मनाने के प्रयास कई बार हो चुके हैं कि एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए और नया मुख्यमंत्री बनाया जाए। 2017 में वह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने थे। वहीं पिछले साल 3 मई को मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू हुई।

राजस्थान के कारोबारी का चीन में अपहरण....फिर मर्डर

किडनैपर्स ने 1 करोड़ रुपये की फिरोती मांगी

जालौर। (एजेंसी)

राजस्थान के जालौर जिले के बिजनेसमैन का चीन में अपहरण हुआ है। किडनैपर्स ने बिजनेसमैन को छोड़ने की एवज में 1 करोड़ रुपये की फिरोती मांगी। फिरोती की रकम नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर दी गई। चीन में हत्या का शिकार हुआ था राजस्थान की सतीश कुमार (26) मुंबई में मोबाइल का कारोबार करता था। इसका परिवार भीनमाल में कृषि फार्म में रहता है। सतीश चीन से सामान खरीदकर मुंबई में होल्सेल में दुकानदारों को बेचता था। इसके लिए उसका महीने या दो महीने चीन आना जाना लगा रहता था। वह जून के महीने में भी चीन गया था। वहां बीते 21 जून को उसका अपहरण कर लिया गया।

सतीश के परिजनों के मुताबिक

माध्यम से कानूनी प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कारोबारी की हत्या की यह वारदात आठ दिन पहले हुई थी। हत्या का शिकार हुआ कारोबारी सतीश कुमार (26) मुंबई में मोबाइल का कारोबार करता था। उसका परिवार भीनमाल में कृषि फार्म में रहता है। सतीश चीन से सामान खरीदकर मुंबई में होल्सेल में दुकानदारों को बेचता था। इसके लिए उसका महीने या दो महीने चीन आना जाना लगा रहता था। वह जून के महीने में भी चीन गया था। वहां बीते 21 जून को उसका अपहरण कर लिया गया।

किडनैपर्स ने उससे 1 करोड़ रुपये की फिरोती डिमांड की। 24 जून तक सतीश कुमार का मोबाइल चालू था। वह परिजनों को खुद के अपहरण और अपहरणकर्ताओं की मांग के बारे में बता रहा था। फिरोती की रकम मिलने का व्यापारी को तक पहुंचाने के लिए कहा गया था। उसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। 24 जून को उसके भाई के मोबाइल पर सूचना दी गई की सतीश कुमार नाम के शख्स को चीन के ग्वांगजो सिटी में लाश मिली है। यह सुनकर सतीश के परिवार में कोहराम मच गया। सतीश कुमार के तीन रिश्तेदार चीन जाने के दिखे पहुंच गए। वहां उन्होंने सांसद चौधरी से



उनके आवास पर मुलाकात कर घटना के बारे में बताया।

सांसद ने मामले को गंभीरता से लेकर तीनों रिश्तेदारों को चीन का वीजा आवेदन करवाकर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क साधा। विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र मेल कर चीन जाने का



वीजा और बांडी भारत लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। सतीश के परिजन मोहनलाल माली ने बताया कि सतीश कुमार के अपहरण और हत्या में चीन के साथ साथ कुछ भारतीय लोगों की मिलीभगत की आशंका है।

मिड डे मील योजना पर नजर: हरियाणा में निकले 4 लाख फर्जी छात्र, सीबीआई ने किया मामला दर्ज

नई दिल्ली। (एजेंसी)

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में एडमिशन को लेकर फर्जीबाड़े के मामले में सीबीआई अब एक्शन मोड में आ गई है। 2016 में पकड़े गए चार लाख फर्जी छात्रों के मामले में एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

इससे पहले सीबीआई ने सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि जांच के लिए भारी जनशक्ति की आवश्यकता हो

सकती है और जांच राज्य पुलिस को दी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने हाल ही में याचिका खारिज कर दी जिसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। हाईकोर्ट को 2016 में सूचित किया गया था कि आंकड़ों के सत्यापन से पता चला है कि सरकारी स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में 22 लाख छात्र थे, लेकिन वास्तव में केवल 18 लाख छात्र ही पाए गए और चार लाख फर्जी दाखिल थे।

अदालत को यह भी बताया गया

कि समाज के पिछड़े या गरीब तबके के छात्रों को स्कूलों और मिड डे मील योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ लाभ दिए जा रहे हैं। उच्च न्यायालय ने राज्य सतर्कता विभाग को चार लाख फर्जी छात्रों के नाम पर धन की संदिग्ध हेराफेरी की जांच के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया था। पीठ ने जिम्मेदारी तय करने और दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। सतर्कता ब्यूरो की सिफारिशों पर राज्य में सात

एफआईआर दर्ज की गईं। हाईकोर्ट ने अपने 2019 के आदेश में कहा था कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच बहुत धीमी है। इसके बाद इसने उचित और त्वरित जांच के लिए मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया।

इसने राज्य सतर्कता विभाग को 2 नवंबर 2019 को अपने आदेश के एक सप्ताह के भीतर सभी दस्तावेज सौंपने को कहा था और सीबीआई को तीन महीने के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

राहुल ने हेमंत से फोन पर जमानत मिलने का किया स्वागत

- नेता प्रतिपक्ष राहुल ने कहा, राजनीतिक दुर्भावना से की गई थी गिरफ्तारी

नई दिल्ली। (एजेंसी)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने का स्वागत किया और उनसे फोन पर बात की। गांधी ने कहा कि सोरेन की गिरफ्तारी बदले और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित थी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी बदले और राजनीतिक दुर्भावना से की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत देने के फैसले का हम स्वागत करते हैं- सोरेन जी से फोन पर बात करके अपनी खुशी जाहिर की। राहुल गांधी ने

कहा कि जो संविधान की रक्षा की भावना लेकर चलते हैं, सत्य खुद उनकी रक्षा करता है। बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को जमानत दे दी जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। अदालत ने सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला 13 जून को सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति रॉन मुखोपाध्याय की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये के जमानती मुचलके और इतनी ही राशि की दो प्रतिभूति के



साथ जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।

राज्यपाल बोस ने ममता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया

कोलकाता। (एजेंसी)

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.बी. आनंद बोस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। सूत्र ने बताया कि इसके पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि महिलाओं ने शिकायत की थी कि वे राजभवन में होने वाली गतिविधियों के कारण वहां जाने से डरती हैं। राज्यपाल बोस ने ममता की टिप्पणियों की आलोचना कर कहा कि जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गलत और बदनामी वाली धारणा न बनाएं।

सूत्र ने कहा कि बंगाल के राज्यपाल ने भी इसी तरह की टिप्पणी करने के लिए कुछ टीएमसी नेताओं के खिलाफ

मानहानि का मुकदमा दायर किया है। सूत्र ने बताया, राज्यपाल बोस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख कर मुख्यमंत्री ममता और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया।

2 मई को, राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने भी जांच शुरू की थी।

इस बारे में टीएमसी की राज्यसभा सांसद डोला सेन ने कहा कि वह पार्टी नेतृत्व से चर्चा किए बिना इस मामले पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि वास्तव में क्या हुआ, यह जानने



के लिए मुझे अपनी पार्टी के नेतृत्व से बात करनी होगी। सेन ने कहा, यह काफी संवेदनशील मामला है।

वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि बोस ने सही फैसला लिया है। उन्हें यह फैसला बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। मैं इसके लिए उनका पूरा समर्थन करता हूं। वरिष्ठ माकपा नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि बोस और बनर्जी के बीच टकराव से राज्य को कोई मदद नहीं मिल रही है। चक्रवर्ती ने कहा, यह वास्तव में हमें नुकसान पहुंचा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

पेपर लीक मामला: सीबीआई आरोपियों से पूछताछ करने बेउर जेल पहुंची

पटना। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 आरोपियों से पूछताछ की है। पूछताछ के लिए सीबीआई बेउर जेल पहुंची। सभी आरोपियों के वकील भी बेउर जेल पहुंचे गए। आरोपियों के वकील की मौजूदगी में ही पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि नीट पेपर लीक मामले में यह अब तक की सबसे बड़ी पूछताछ है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई देश के कई राज्यों में जाकर सन्दिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है।

अब स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में शुरु होंगी प्राइमरी स्तर की कक्षाएं

जयपुर। राजस्थान में स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में अब प्राइमरी स्तर की कक्षाएं शुरु की जाएंगी। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सीएम भजनलाल ने स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में प्राइमरी स्तर की कक्षाएं शुरु करने के लिए करीब 10 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दे दी है साथ ही अध्यापन कार्य के लिए तृतीय श्रेणी अध्यापक के तीन अतिरिक्त पद हरेक स्कूल के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इन पदों पर शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों की इंटरव्यू लेकर प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सीएम भजनलाल के इस फैसले से राज्य में संचालित हो रहे 134 मॉडल स्कूलों में प्राइमरी कक्षाओं के लिए निर्मित भवनों में अब शिक्षण कार्य सुचारु रूप से हो सकेगा।

बिजली गिरने से महिला समेत चार की मौत, मवेशी भी हुए शिकार

फतेहपुर। यूपी के फतेहपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई। वहीं चार बकरियां भी इसका शिकार हुई हैं। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आकाशीय बिजली गिरने के बाद बिजली के मुताबिक किशनपुर थाना क्षेत्र के झुरहापुर मजरे गढ़ा गांव निवासी रामकृपाल की पत्नी कैरी देवी (50) बकरियां को चराने गई थी। इस दौरान अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। बारिश से बचने महिला पेड़ के नीचे छिप गई, तभी गरज और चमक के साथ उस पर बिजली गिर गई। इस हादसे में महिला की झुलसने से मौत पर ही मौत हो गई। वहीं खेतों में चर रही चार बकरियां भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। उधर, गाजीपुर थाना क्षेत्र के देवलान गांव निवासी कैलाश पुत्र रामपाल (48) और 42 वर्षीय सीताराम अपने-अपने मवेशियों को लेकर चराने जंगल गए थे। इस बीच आकाशीय बिजली गिरने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। एक साथ दो मौतों से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं गांव में मातम छा गया। इसी तरह सुल्तानपुर घोघ थाना क्षेत्र के अस्तुपुर गांव में अचानक बारिश के बीच गाज गिरने से एक 16 वर्षीय किशोरी की भी मौत हो गई। बिजली के कहर के शिकार इन सभी शवों को संबंधित थाना क्षेत्रों की पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बंगाल एसटीएफ ने चेन्नई से किया अनवर शेख को गिरफ्तार

चेन्नई। पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन शहादत-ए-अल-हिक्मा से जुड़े होने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान अनवर शेख के रूप में हुई है। वह चेन्नई में राजमिस्त्री का काम करता था। पुलिस अधिकारी ने बताया, हम अनवर को कोलकाता वापस ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि शेख का नाम उसी संगठन के गिरफ्तार किए गए पांच लोगों से पूछताछ करने के बाद सामने आया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को केंद्रित विज्ञान का एक छात्र भी शामिल है। अधिकारी ने बताया कि इन पांचों को पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए सभी लोग आतंकी संगठन के लिए भेज आये को शामिल कर रहे थे।

केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ...आप का हल्लाबोल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ शनिवार को भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी के सभी सांसद, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे बीजेपी कार्यालय तक मार्च कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के लिए आप कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया था जिसमें लिखा था, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग बंद करें। यह विरोध तब हुआ है, जब सीबीआई शनिवार को केजरीवाल को अदालत में पेश करने वाली है, क्योंकि उनकी तीन दिन की हिरासत खत्म हो रही है। शराब नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए केजरीवाल शाम 7 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने वाले हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित सलिलता के सिलसिले में केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है, वहीं ईडी कथित मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच कर रही है।

भाजपा की महिला नेत्री को निर्वस्त्र कर पीटा और बाल पकड़कर घसीटा

कोलकाता। (एजेंसी)

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासी बवाल मचा हुआ है। कूच बिहार में एक 32 साल की महिला को निर्वस्त्र करके पिटाई करने के मामले में सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी का दावा है कि पीड़िता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की उपाध्यक्ष है। बीजेपी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में अपनी टीम भेजकर घटना की जांच करवाई जाए। वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर संकीर्ण राजनीति करने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि गलत जानकारी

देकर मामले को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही है। जबकि यह एक पारिवारिक विवाद था। पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक विवाद की वजह से पड़ोसियों ने उनकी बेटी पर हमला किया। पड़ोसी से ही इनकार कर दिया। बाद में एसपी के दखल के बाद शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने पीड़िता के ही एक रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम एफआईआर में भी नहीं था। वहीं राज्य में महिला और बाल विकास मंत्री शशि पॉन्जा ने कहा कि बीजेपी संकीर्ण राजनीति पर उतर आई है।

भ्रष्टाचार प्रतियोगिता में & भ्रष्टाचार की जानकारी देने

National Rights Group
Youtube Channel

krantisamay@gmail.com

9879141480

fight against corruption india

भारत में भ्रष्टाचार
के खिलाफ लड़ाई